7 जनवरी 2026
बुधवार

केशव टाइम्स

डिजिटल संस्करण

तीस लाख की ड्रग्स के साथ असम से गिरफ्तार हुआ बलिहार का वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, बड़े नेटवर्क का खुलासा

2

प्रमुख खबरें : दिल्ली ■ पटना ■ बक्सर ■ शाहाबाद ■ मगध ■ सारण ■ मिथिलांचल ■ चंपारण ■ पूर्वांचल ■ लखनऊ

आपकी आवाज

एक नजर

हराम का पैसा मिले तो इसे लो और शौचालय बनवाने में लगाओ

लातूर । ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि अगर चुनाव के दौरान सियासी दलों की ओर से अनैतिक पैसा दिया जा रहा है, तो इसे स्वीकार करें और उसका इस्तेमाल शौचालय बनाने में करें। ओवैसी लातूर नगर निगम चुनाव के लिए आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में ओवैसी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी मोदी सरकार की नीति पर हमला किया और वक्फ (संशोधन) अधिनियम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी दलों ने तभी मतदाताओं में पैसे बांटने शुरू किए, जब एआईएमआईएम ने चुनाव में हिस्सा लिया। अगर हम उम्मीदवार नहीं उतारते, तो पैसे नहीं बांटे जाते। पैसा लो और अगर यह अनैतिक या 'हराम' लगे, तो शौचालय बनाने में लगाओ। ओवैसी ने मुसलमानों से मजबूत राजनीतिक नेतृत्व बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर समुदाय के पास सियासी ताकत है, सिवाय अल्पसंख्यकों के।

गढ़चिरौली नक्सली हमले के आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के गडचिरोली नक्सली आईईडी हमले से जुड़े मामले में आरोपी कैलाश रामचंदानी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी और मामला देशभर में काफी चर्चित रहा था। शीर्ष अदालत ने यह राहत लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे में हो रही देरी को देखते हुए दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि रामचंदानी 29 जून 2019 से जेल में है और अब तक मामले में आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमानत का कड़ा विरोध किया। एनआईए की ओर से कहा गया कि आरोपी की भूमिका अहम थी और उसी की सूचना पर आईईडी विस्फोट किया गया।

उत्तर प्रदेश में कटे 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम

- विधानसभा चुनावों में हजार-पांच सौ वोटों के अंतर से भी अनेक सीटों पर हार-जीत के परिणाम होते हैं तय
- एसआईआर आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा से औसतन 70-71 हजार वोट काटे गए

एजेंसी। लखनऊ

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का एसआईआर डाटा जारी कर दिया है। प्राथमिक रूप से जारी किए गए आंकड़ों में यूपी के करीब 18 प्रतिशत मतदाताओं (2.89 करोड़) का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। मोटे तौर पर प्रदेश का हर पांचवां मतदाता इस बार सूची से बाहर हो गया है। विधानसभा चुनावों में हजार-पांच सौ वोटों के अंतर से भी अनेक सीटों पर हार-जीत के परिणाम तय होते हैं। लेकिन एसआईआर आंकड़ों में हर विधानसभा से औसतन 70-71 हजार वोट काटे गए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सभी सियासी दल इन आंकड़ों के जारी होने के बाद अपनी जीत-हार को लेकर गुणा-भाग करने में जुट गए हैं। सभी दल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के बाद नए समीकरणों में यह किसके लिए लाभ और किसके लिए नुकसान का सौदा साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर को लेकर अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। भाजपाई खेमे में शहरी क्षेत्रों से मतदाताओं के नाम कटने को लेकर बड़ी चिंता है।

सबका साथ, सबका विकास की नीयत से करते हैं काम

भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने अमर उजाला से कहा कि मतदाता सूची में सुधार को किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार हो या यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार सबने समाज के हर वर्गों का विकास किया है और किसी के साथ धर्म-क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। भाजपा देश के हर नागरिक, हर वोटर को अपना मानकर काम करती है। उन्होंने कहा कि सबको अपना मानने और सबके लिए काम करने की सोच का ही कारण है कि भाजपा को हर जाति, हर वर्ग के मतदाता का प्यार मिल रहा है। जो विपक्षी दल जनता के बीच काम नहीं करते हैं और केवल कभी संविधान और कभी एसआईआर पर भ्रम पैदा कर चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें बिहार की तरह यूपी में भी हार का ही सामना करना पड़ेगा।

भाजपा आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप से एसआईआर करा रहा चुनाव आयोग

एजेंसी। गंगानगर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग राज्य में एसआईआर अभ्यास को कराने के लिए भाजपा के आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग 'हर तरह के गलत तरीके' अपना रहा है। न्होंने कंहा, एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। वह योग्य मतदाताओं को मृत घोषित कर रहा है और बुजुर्ग, बीमार और असहाय लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। वह इस काम के लिए भाजपा के आईटी सेल के बनाए मोबाइल एप का इस्तेमाल कर रहा है। यह अवैध, असांविधानिक और अलोकतांत्रिक है। ऐसे नहीं चल सकता। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो की ओर से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब उनकी पार्टी के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को कराने के लिए आयोग ने मनमाने और प्रकिया के खिलाफ कदम उठाए हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा प्रसारित

जेएनयू में लगे मोदी-शाह की कब्र खुदेगी के नारे

एजेंसी। नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात हुए एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोदी-शाह की कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ नारे लगाए। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदू सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस आयुक्त (डीसीपी) को पत्र लिखकर इन नारों को राष्ट्र विरोधी, जानलेवा धमकी और हिंसा भड़काने वाला बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में गुप्ता ने बताया कि सोमवार को उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट के जमानत फैसले के विरोध में जेएनयू कैंपस में देर रात जुटे छात्रों ने ये नारे लगाए, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उन्होंने इसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत अपराध करार देते हुए कहा कि यह सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ मौत की धमकी है, जो सार्वजनिक शांति भंग करने और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास है। गुप्ता ने वीडियो लिंक और स्क्रीनशॉट संलग्न कर पुलिस से नारेबाजों की पहचान, गिरफ्तारी और प्रदर्शन के आयोजकों की जांच की मांग की। हिंदू सेना प्रमुख ने पत्र में जेएनयू को बार-बार श्भारत-विरोधी बयानबाजी का केंद्रश बताते हुए चेतावनी दी कि यदि इन पर सख्त कार्रवाई न हुई तो यह देश की एकता-अखंडता के लिए खतरा बनेगा। दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी कार्यालय में आज यह पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर रिसीविंग साइन और तारीख दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक नारेबाजी के समय जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश और सचिव सुनील मौके पर मौजूद थे. इसके अलावा, वामपंथी संगठनों से जुड़े कई छात्र भी वहां इकट्ठा हुए थे. पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

जेएनयू में नारेबाजी पर सियासी घमासान

दिल्ली के जेएनयू कैंपस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के बाद हुए प्रदर्शन में विवादित नारेबाजी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, श्मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी प्रदर्शन होंगे तो क्या बचेगा। ये लोग देश, संविधान और कानून का सम्मान नहीं करते। ये अलगाववादी सोच वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा इन लोगों के पीछे दिखाई

यह नाराजगी का तरीका है- कांग्रेस

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यह नाराजगी जताने का तरीका है। जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गुस्सा है। उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वे मुस्लिम हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में मोदी-शाह विरोधी नारों पर कहा कि विपक्ष इस टुकड़े-टुकड़े गिरोह का समर्थन करता है। ये सभी राष्ट्रविरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। जेएनयू टुकड़े-टुकड़े गिरोह का अड्डा बन गया है। मोदी और शाह की कब्र खोदने वाले ये लोग खुद ही कब्र में जा चुके हैं।बता दें कि प्रदर्शन जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ था, जिसमें जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र मौजूद थे।

जम्मू से दिल्ली तक कड़ाके की ठंड, यूपी-एमपी और बिहार में कोहरे का कहर

एजेंसी। नई दिल्ली

देशभर के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर-पश्चिमी, मध्य, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के हिस्सों में आने वाले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के मुताबिक, 7 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड , पश्चिम बंगाल, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में शीतलहर पड़ने की प्रबल संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 07 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घने कोहरे छाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, यहां अगले 48 घंटों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल सुबह से शाम तक कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है , लेकिन कोहरे में कमी और दिन में धूप निकलने से लोगों को दिन के समय राहत भी मिली है। कुल मिलाकर यहां अभी ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

कुपोषण मुक्त भारत के लिए सरकार ने कसी कमर

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कारपोरेट कंपनियों को सलाह दी है कि सामाजिक जिम्मेवारी यानी सीएसआर को केवल कानून की बाध्यता न मानें और इसे दो प्रतिशत की सीमा में न बांधें। उन्होंने कहा कि कानून में तय दो प्रतिशत को न्यूनतम स्तर समझना चाहिए, न कि अधिकतम। कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने सरकार के साथ ही कारपोरेट जगत, समाज और आम लोगों से भी आगे आने की अपील की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित पोषण पर राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को आंदोलन बनाना होगा। जब तक हर स्तर पर सामूहिक प्रयास नहीं होंगे, तब तक देश को कुपोषण-मुक्त बनाना मुश्किल है।उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब देश का हर बच्चा स्वस्थ होगा। गोयल ने कहा कि सीएसआर कोई बोझ नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ करने का अवसर है। खासकर कुपोषण जैसी समस्या में सीएसआर की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने समझाया कि पोषण पर खर्च करना दरअसल देश के भविष्य में निवेश करना है। स्वस्थ बच्चे ही भविष्य में अच्छे कर्मचारी, अच्छे नागरिक और जिम्मेदार उपभोक्ता बनेंगे। इससे कंपनियों और देश, दोनों को लाभ होगा।

बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

■ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित

केटी न्यूज/बक्सर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा सोमवार को बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारियों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें जिले में कार्यरत सभी बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) तथा बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 के प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को देना था, ताकि विधि विवादित बालकों एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों का संवेदनशील, कानूनी और मानवीय ढंग से निपटारा किया जा सके। प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक प्रधान दंडाधिकारी सह किशोर न्याय परिषद, बक्सर के श्री हर्षवर्धन सिंह रहे। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के गठन की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिले में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस नोडल पदाधिकारी होते हैं, जबकि प्रत्येक थाना में कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की नामांकन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 की धारा 8 के तहत बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को विधि विवादित बालक से संबंधित सूचना दैनिक डायरी में अंकित करनी होती है तथा प्रारूप-01 के अंतर्गत बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की विस्तृत रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद को उपलब्ध करानी होती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य घटना की वास्तविक स्थिति को समझना, बालक की भूमिका, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करना है, ताकि किशोर न्याय परिषद न्यायोचित निर्णय ले सके। जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर के परामर्शदाता श्री प्रकाश कुमार ने प्रारूप-01 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें बालक की व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, मित्र मंडली, मानसिक स्थिति, आदतें, पारिवारिक परिवेश, अपराध में कथित भूमिका, बालक का किसी गिरोह द्वारा इस्तेमाल, तथा माता-पिता की अपेक्षाओं जैसी जानकारियों का समावेश आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार बालकों को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी और 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय परिषद या बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापन अनिवार्य है। चीफ विधिक सहायता प्रतीक्षा प्रणाली, बक्सर के श्री विनय कुमार सिंह ने विधि सह परीक्षा अधिकारी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किशोर न्याय परिषद के आदेश पर दो सप्ताह के भीतर प्रारूप-06 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट बालक की सामाजिक, पारिवारिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी विशेषज्ञों ने समाधान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यालय कर्मी सुधीर कुमार, दीपेश कुमार, सुमित कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार रवानी, मोहम्मद अकबर अली सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण को पुलिस पदाधिकारियों ने अत्यंत उपयोगी एवं मार्गदर्शक बताया।

तीस लाख की ड्रग्स के साथ असम से गिरफ्तार हुआ बलिहार का वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, बड़े नेटवर्क का खुलासा

■ लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी में सक्रिय था गिरफ्तार आरोपित, बार-बार पुलिस को दे रहा था चकमा

केटी न्यूज/बक्सर

असम के मोरियानी रेलवे स्टेशन पर हुई एक बड़ी कार्रवाई ने न सिर्फ अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को बेनकाब किया है, बल्कि स्थानीय राजनीति और अपराध के खतरनाक गठजोड़ पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने विवेक एक्सप्रेस डाउन ट्रेन से 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मादक पदार्थों की खेप के साथ बिहार के बक्सर जिले के एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार गांव निवासी राजू कुमार राम पिता स्व. रामनाथ राम के रूप में हुई है, जो वर्तमान में एक वार्ड पार्षद का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। असम पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई नियमित जांच के दौरान की गई, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया और तलाशी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई।

होजाई से तिनसुकिया तक फैला था सप्लाई नेटवर्क

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह ड्रग्स खेप असम के होजाई क्षेत्र से तिनसुकिया की ओर ले जाई जा रही थी, जहां से इसे ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों में खपाने की योजना थी। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है, जिससे इस नेटवर्क के बड़े और संगठित होने के संकेत मिलते हैं।

राजनीतिक पहचान की आड़ में काला कारोबार

पुलिस सूत्रों का कहना है कि राजू कुमार राम लंबे समय से ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल ह्लसुरक्षा कवचह्व के रूप में कर रहा था। आरोप है कि बीते दो वर्षों में उसने अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की संपत्ति खड़ी की। गांव में कीमती जमीन खरीदकर आलीशान मकान बनाने के अलावा बलिया, भरौली, डुमरांव समेत कई स्थानों पर संपत्ति निवेश की जानकारी भी सामने आ रही है। लग्जरी कारों का शौक और दिखावटी जीवनशैली अब जांच के दायरे में है।

भाई पर भी संरक्षण देने का आरोप

मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी के भाई पप्पू राम पर भी तस्करी नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप सामने आए। सूत्रों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर प्रभाव और संपर्कों के जरिए नेटवर्क को सुरक्षित रखने में उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पहले भी खुफिया एजेंसियों की नजर में था आरोपी

बताया जा रहा है कि डुमरांव के तत्कालीन एसडीपीओ आफाक अख्तर को पहले भी राजू राम की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। उसे पकड़ने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलने में सफल रहा। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा आम रही है कि वह फर्जी एससी-एसटी मामलों में लोगों को फंसाने, दबाव बनाने और अवैध उगाही जैसे कृत्यों में भी संलिप्त रहा है।

अब संपत्ति जब्ती की तैयारी

फिलहाल असम पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर पूरे ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस गिरफ्तारी को अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक पहचान अपराधियों के लिए ढाल बनती जा रही है और क्या स्थानीय स्तर पर समय रहते कार्रवाई होती, तो यह नेटवर्क पहले ही ध्वस्त किया जा सकता था। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में जांच के और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक नजर

वसूली और धमकी के आरोप में यातायात निरीक्षक पर अदालत सख्त, नोटिस जारी

बक्सर। बक्सर में यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए न्यायालय ने यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामला अधिवक्ता पवन कुमार राय से जुड़ा है, जिनके ट्रैक्टर को सिंडिकेट मोड़ के पास यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद ने कानूनी रूप ले लिया। अधिवक्ता राघव कुमार पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे अन्य अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि यातायात पुलिस निरीक्षक संजय कुमार उस समय नशे की हालत में थे और ट्रैक्टर संचालन की अनुमति देने के बदले प्रति माह 50 हजार रुपये की अवैध मांग की गई। आरोप है कि मांग का विरोध करने पर निरीक्षक ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने तक की धमकी दी। परिवाद में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान अधिवक्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली का प्रयास किया गया।

एसपी के जनता दरबार का असर: गुहार लगाने के बाद घर बच्चों के साथ फरार हुई महिला बरामद

डुमरांव। नया भोजपुर थाने में सोमवार को आयोजित एसपी के जनता दरबार में स्थानीय गांव निवासी राजकुमार बिंद ने अपनी पत्नी के घर छोड़ फरार होने की गुहार लगाई थी। एसपी ने थानाध्यक्ष को फरार हुई महिला को बरामद करने का निर्देश दिया था। इसके अगले दिन ही पुलिस ने उक्त महिला को उसके दोनों बच्चों के साथ बरामद कर लिया। हालांकि, बरामद होने के बाद भी वह पति के साथ नहीं गई। नियमों के मुताबिक थानाध्यक्ष ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए भेजा है, जहां धारा 164 के तहत उसका बयान होगा। उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर ही उसके आगे का रास्ता तय होगा। एसपी के जनता दरबार में गुहारे लगाने के अगले दिन ही पुलिस द्वारा महिला को बरामद कर लिए जाने के बाद अन्य फरियादियों में इस बात की उम्मीद जगी है कि अब जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा।

तियरा बाजार में ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी, एक ही पैटर्न पर वारदात से संगठित गिरोह की आशंका

■ ज्वेलर्स दुकानों पर सिलसिलेवार चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी का डीवीआर ले उड़े चोर, पुलिस के लिए बनी चुनौती

केटी न्यूज/राजपुर

राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपये के गहने चोरी होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अज्ञात चोरों ने न सिर्फ कीमती आभूषणों पर हाथ साफ किया, बल्कि साक्ष्य मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। इस तरीके ने चोरी के एंगल को और गंभीर बना दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खीरी निवासी राहुल सेठ की तियरा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है। सोमवार की शाम रोज की तरह दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। देर रात जब बाजार पूरी तरह सुनसान हो गया, तभी चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर भीतर घुसे चोरों ने सोने-चांदी के कीमती गहने समेटे और फरार हो गए। सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का दरवाजा खुला देखा तो दुकानदार को सूचना दी गई।

दुकान पर पहुंचे राहुल सेठ ने देखा कि सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है और गहने गायब हैं। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच-पड़ताल शुरू की। पीड़ित दुकानदार ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर ले गए हैं, जिससे पूरी वारदात के फुटेज गायब हो गए।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि तियरा बाजार में यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते दिनों दो अन्य ज्वेलर्स दुकानों के ताले भी तोड़े गए थे। एक दुकान से चोरी हो गई थी, जबकि दूसरी दुकान में चौकीदार की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। वहीं बन्नी बाजार में भी बर्तन और ज्वेलर्स की दुकानों से चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

लगातार एक ही तरह से हो रही वारदातों ने संगठित चोर गिरोह की आशंका को मजबूत कर दिया है। राजपुर और धनसोई पुलिस अपने-अपने स्तर से जांच में जुटी है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस की निष्क्रियता और बढ़ती चोरी की घटनाओं ने व्यापारियों और आम लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बाजारों में चर्चा है कि यदि जल्द खुलासा नहीं हुआ, तो चोरों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं।

हल्का कार्यालय में खुली लापरवाही की परतें, एसडीएम के औचक निरीक्षण से मचा प्रशासनिक हड़कंप

■ लैंड रिकॉर्ड, आवेदन पंजी और लैंड बैंक कार्य ठप, एक सप्ताह की मोहलत के साथ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

केटी न्यूज/डुमरांव

भोजपुर कदीम पंचायत अंतर्गत हल्का कार्यालय में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एसडीएम राकेश कुमार ने अचानक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रशासन की जमीनी हकीकत सामने आ गई, जहां कागजों पर चल रहे सिस्टम और वास्तविक कार्यों के बीच भारी अंतर पाया गया। राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की स्थिति देखकर एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताई और इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि भूमि से संबंधित कई आवश्यक रिकॉर्ड अद्यतन नहीं हैं। लैंड रिकॉर्ड संधारण पंजी, आवेदन पंजी और अन्य अभिलेख लंबे समय से अपडेट नहीं किए गए थे। इससे भी गंभीर बात यह रही कि जनता दरबार और कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर राजस्व कर्मचारी राजू कुमार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, आम लोगों को महीनों से अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी लैंड बैंक योजना से जुड़े कार्य भी आधे-अधूरे पाए गए। एसडीएम ने इसे प्रशासनिक उदासीनता का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि भूमि रिकॉर्ड का सही और समयबद्ध संधारण शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी कुमार दिनेश को भी एसडीएम के सख्त तेवरों का सामना करना पड़ा। एसडीएम ने सवाल उठाया कि यदि नियमित समीक्षा की जा रही होती, तो स्थिति इतनी बदहाल कैसे हो जाती। उन्होंने समीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। एसडीएम राकेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही भूमि रिकॉर्ड, आवेदन पंजी और लैंड बैंक से संबंधित सभी कार्य पूर्ण रूप से अद्यतन किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। औचक निरीक्षण के बाद से ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व कार्यालयों में दस्तावेज दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों में जवाबदेही को लेकर बेचैनी साफ देखी जा रही है।

राजपुर विधायक से मिले आईईएसएम बक्सर के जांबाज सैनिक, सैनिक वेलफेयर कार्यालय की रखी मांग

■ विधायक संतोष निराला ने दिया सकारात्मक आश्वासन, सैनिकों व वीरांगनाओं में खुशी

केटी न्यूज/बक्सर

इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) बक्सर के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजपुर विधायक संतोष कुमार निराला से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सैनिकों ने राजपुर प्रखंड क्षेत्र में सैनिक वेलफेयर तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर झंडोत्तोलन के लिए एक स्थायी सैनिक कार्यालय की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि राजपुर और इटाढ़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक एवं वीरांगनाएं निवास करती हैं, लेकिन अब तक उनके लिए कोई समर्पित कार्यालय उपलब्ध नहीं है। इससे सैनिकों को अपनी समस्याओं के समाधान, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सामाजिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विधायक संतोष निराला ने सैनिकों की इस मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार एवं जनप्रतिनिधि सदैव प्रतिबद्ध हैं और इस मांग को पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

आईईएसएम बक्सर के जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्या सागर चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मांग वर्षों से लंबित है। पूर्व में इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बक्सर जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया था। सैनिकों ने एक बार फिर लिखित आवेदन के माध्यम से विधायक को सैनिक कार्यालय की आवश्यकता से अवगत कराया है।

विधायक से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद राजपुर एवं इटाढ़ी क्षेत्र के सैनिकों और वीरांगनाओं में खुशी की लहर देखी गई। सभी ने इस पहल को सैनिक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और विधायक का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आईईएसएम बक्सर के जिला उपाध्यक्ष सूबेदार विद्या सागर चौबे, कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर आर. सिंह, उप कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी गणेश सिंह एवं सुदामा प्रसाद, तकनीकी अधिकारी धनंजय दुबे, संयोजक रामनाथ सिंह, इटाढ़ी प्रखंड अध्यक्ष हरिहर सिंह, राजपुर प्रखंड अध्यक्ष चंद्रजीत सिंह, डायरेक्टर हाकिम प्रसाद, उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, उप चेयरमैन राम किसान सिंह, सचिव राम इकबाल राय के साथ-साथ भाजपा राजपुर प्रखंड अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह एवं भाजपा कार्यकर्ता धनंजय मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

Mob: 9122226720
कुमार आर्थोपेडिक्स क्लिनिक
सुमित्रा महिला कॉलेज से पूरब, बेतवानी मोड़, डुमराँव
डा. बिरेन्द्र कुमार
आर्थोपेडिक सर्जन
हड्डी, नस, गठिया रोग विशेषज्ञ
डा. एस.के. अम्बष्ठ
M.B.B.S (MKCC, ODISHA)
MD (Derma & Cosmetology),
KMC Manipal (Gold Medalist)
चर्म रोग, कुष्ट रोग, गुप्त रोग, सौंदर्य विशेषज्ञ
प्रत्येक मंगलवार
डा. अरूण कुमार
जेनरल एण्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन
(M.B.B.S, D.NB. (New Delhi)
पेट रोग विशेषज्ञ
प्रत्येक गुरूवार

जल-जीवन-हरियाली दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता में छात्राओं ने मारी बाजी

■ लाइव राज्य स्तरीय परिचर्चा से जुड़ा बक्सर, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पर दिया गया बल

केटी न्यूज/बक्सर

जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत माह के प्रथम मंगलवार को जिला स्तर पर जल-जीवन-हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने की। इस अवसर पर राज्य स्तरीय परिचर्चा से लाइव जुड़कर जिले के पदाधिकारियों ने अभियान की प्रगति, क्रियान्वयन और इसके प्रभावों पर विचार-विमर्श किया। परिचर्चा का मुख्य विषय जल-जीवन-हरियाली के क्रियान्वयन एवं प्रभाव रहा, जिसमें विभिन्न विभागों की भूमिका, जनसहभागिता और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्तर से मिले मार्गदर्शन को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने पर बल दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन है, जिसमें आम नागरिकों की भागीदारी सबसे अहम है। उन्होंने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में जल-जीवन-हरियाली से जुड़े सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय निर्देश के तहत शिक्षा विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई थीं। इसी क्रम में जल-जीवन-हरियाली विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रखंड स्तर से चयनित प्रतिभागियों के बीच 22 दिसंबर को जिला स्तर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएम श्री इंदिरा प्लस टू उच्च विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा पलक कुमारी ने प्राप्त किया, जिन्हें 6000 रुपये का चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। द्वितीय स्थान एमपी उच्च विद्यालय, बक्सर की कक्षा 9 की छात्रा गोल्डी कुमारी को 5000 रुपये तथा तृतीय स्थान प्लस टू नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय, बक्सर की कक्षा 9 की छात्रा शिखा कुमारी को 4000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। सभी पुरस्कार जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के हस्ताक्षरयुक्त प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, जिला मिशन प्रबंधक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। कार्यक्रम के समापन पर जल-जीवन-हरियाली अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और इसके लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया गया।

एक नजर

कोचिंग के लिए घर से निकली छात्रा फरार, मां ने पुलिस से लगाई गुहार

डुमरांव। डुमरांव के एक मोहल्ले से कोचिंग जाने की बात कह दसवीं कक्षा की एक छात्रा फरार हो गई है। जब वह बहुत देर तक नहीं लौटी तथा उसका मोबाइल भी बंद आने लगा तब घरवालों को चिंता हुई तथा आस पड़ोस समेत सभी संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसकी मां ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन दिया है। थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने जिक्र की है कि उसकी बेटी करीब घर से कोचिंग पढ़ने की बात कह निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आई है। आवेदन मिलते ही पुलिस मामले की जांच व किशोरी को बरामद करने के प्रयास में जुट गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला के आवेदन में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। वहीं, जानकारों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है।

डुमरांव राजवाहा मार्ग का निर्माण हुआ शुरू, अनुमंडलवासियों को होगी सहूलियत

डुमरांव। वर्षों से जर्जर पड़े डुमरांव राजवाहा मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस रोड के बनने से अनुमंडल के चार प्रखंड के लोगों को आने-जाने मे काफी सहूलियत मिलेगी। इतना ही नहीं इस रोड का जुड़ाव सिधे फोरलेन से जुड़े होने के कारण लोग कम दूरी तय करते हुए डुमरांव, चौंगाई, केसठ और नावानगर आ-जा सकते हैं। इन चार प्रखंड के लोग डुमरांव शहर के बीचोबीच से गुजर रही एनएच से होते हुए अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय, बीएमपी आते-जाते हैं। इस राजवाहा रोड के बन जाने के कारण कम समय और कम दूरी तय कर इन संस्थानों में पहुंच सकते हैं। मालूम हो कि इस रोड से दो पुलियों का जुड़ाव है, जिसकी रेलिंग और आगे का भाग टूट चुका है। इस दोनों पुलिया का निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है। पुलिया और सड़क का निर्माण हो जाने के बाद शहर में लोगों को आने-जाने में जो भय बना हुआ था, जल्द ही दूर हो जाएगा। इस तरह से पुलिया और रोड के बनना शुरू हो जाने से लोगों में काफी खुशी है। इन सभी संस्थानों में आने के लिये एनएच से लोग पहले डुमरांव शहर में आते हैं, फिर ऑटो पकड़ छठिया पोखरा तक आते हैं, फिर वहा से इन संस्थानों में आना पड़ता था। ऐसे में समय की बबार्दी के साथ आर्थिक बोझ भी पड़ता था। रोड और पुल बन जाने से इस भार से लोग मुक्त हो जाएंगे।

पंचायत स्तर पर कैंप से किसानों को मिली बड़ी सुविधा

नावानगर। किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित होने से बचाने और उन्हें एकीकृत डिजिटल पहचान से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 6 जनवरी से 9 जनवरी तक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर किसानों का ई-केवाईसी एवं फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिससे किसानों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को नावानगर प्रखंड के आथर, बाबूगंज इंग्लिश, कड़सर, वैना, अतिमी पंचायत सहित केसठ प्रखंड के रामपुर एवं केसठ पंचायतों में आयोजित कैंपों में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कैंप में मौजूद कृषि कर्मियों द्वारा किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी के महत्व की जानकारी दी गई और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। किसानों का कहना है कि पंचायत में कैंप लगने से समय और पैसे दोनों की बचत हुई है। पहले जहां ब्लॉक या जिला कार्यालय जाना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही सभी कार्य आसानी से हो रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनने के बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सकेगा। विभागीय अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि जिनका ई-केवाईसी या फार्मर रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, वे तय तिथि के भीतर अपने पंचायत कैंप में पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो।

डा. राजेश मिश्रा पर परिजनों ने लगाये गंभीर आरोप

एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर में सर्दी-बुखार का इलाज कराने पहुंचे अधेड़ की मौत, हंगामा

केटी न्यूज/बक्सर

बक्सर में प्रशासनिक मौन के कारण निजी नर्सिंग होम बेलगाम होते जा रहे है। न उनके लिए कोई नियम है ना कानून एक बोर्ड लगा और खुल गया अस्पताल। कौन-डाक्टर कब आते है जिनका नाम है वो रहते भी है या नही। उनके नाम पर झोलाझाप डाक्टर अपना धंधा चमका रहे है। एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। इसे कोई देखने व जांचने वाला नही है। ऐसा नहीं कि पर्यवेक्षकों की टीम नही है। परन्तु उनकों अपनी जेब गर्म करने से फुरसत मिले तब तो जनता के स्वस्थ्य पर ध्यान देगें।

एक ऐसा ही मामला सामने है गोलंबर-जासो रोड स्थित एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर में इलाज के दौरान एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान अहिरौली गांव निवासी श्रीकृष्ण यादव (55) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि श्रीकृष्ण यादव खांसी, जुखाम और बुखार की शिकायत लेकर सोमवार सुबह करीब 9 बजे खुद रिक्शा से अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसके बावजूद मरीज को भर्ती कर लिया गया। परिजनों के अनुसार, पूरे दिन मरीज को भर्ती रखकर केवल इंतजार कराया गया और दोपहर बाद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मरीज को देखा। परिजनों का आरोप है कि शाम करीब 6 बजे मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। लेकिन रेफर किए जाने के बाद भी बिल भुगतान को लेकर मरीज को काफी देर तक अस्पताल में ही रोके रखा गया। इस दौरान इलाज में देरी होती रही और मरीज की स्थिति और गंभीर हो गई। परिजनों का दावा है कि जब मरीज को एंबुलेंस से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजन और आसपास के लोग अस्पताल परिसर में जुट गए और निजी अस्पतालों की कार्यशैली को लेकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि आजकल कई निजी अस्पतालों में इलाज से पहले मोटी रकम जमा कराने की शर्त रखी जाती है। उसके बाद ही इलाज शुरू किया जाता है। नहीं तो मरीज को सीधे रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई अस्पताल केवल कमाई का जरिया बनकर रह गए हैं, जहां ह्लपहले पैसा, फिर इलाजह्व की नीति अपनाई जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिले में ऐसे कई अस्पताल चल रहे हैं, जहां डिग्रीधारी डॉक्टरों की कमी है, इसके बावजूद धड़ल्ले से इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नगर थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को अपने वाहन से परिजनों के साथ उनके घर तक पहुंचाया। फिलहाल परिजन अस्पताल प्रबंधन से मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद यदि अस्पताल या इलाज में किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों पता चल सकेगा।

बोले एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर के डा. राजेश मिश्रा

डाक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मरीज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत नहीं हुई है। उनको रेफर किया गया था, जहां रास्ते में मौत हो गयी। हमारे अस्पताल में मौत नहीं हुई है। मृतक के बेटे को सुबह से बताया जा रहा था कि आपके पिताजी की तबियत ज्यादा खराब है। आप बाहर लेकर पटना-वाराणसी चले जाइये। परन्तु वह नहीं मान रहा था। अंत में लेकर गया उसी दौरान मौत हो गयी। पूरे मामले में राजनीति की जा रही है। इलाज में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पशुओं से लदी पिकअप वैन जब्त, चार गोवंश बरामद, हिरासत में लिए गए दो

■ राम दास राय थाने की पुलिस को मिली सफलता, दियारा क्षेत्र में नहीं थम रही है पशु तस्करी

केटी न्यूज/सिमरी

रामदास राय के डेरा थाने की पुलिस ने एक पिकअप पर लदे चार गोवंश को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करी के आरोप में पिकअप चालक समेत दो लोगों को हिरासत में ले पूछताछ कर रही है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था।

पिकअप पर गोवंश को भेड़-बकरियों की तरह लादा गया था, जबकि वाहन में फिटनेश प्रमाण पत्र व पशुचारा भी नहीं था। इसके अलावे पशु परिवहन अधिनियम का उल्लंघन भी हुआ है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे पशु तस्करी से ही जोड़कर देख रही है। बरामद गोवंश में अधिकांश दुधारू नहीं है। बता दें कि दियारा क्षेत्र में पशु तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन पूर्व तिलक राय के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव के समीप ग्रामीण युवाओं ने भी तस्करों के साथ चार गोवंश को पकड़ा था। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अभी यह मामला थमा भी नहीं था कि रामदास राय के डेरा थाने की पुलिस ने एक बार फिर से पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इससे यह साबित हो रहा है कि दियारे इलाके में पशु तस्करी का खेल धड़ल्ले से जारी है। इस संबंध में रामदास राय के डेरा थाने के थानाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि एक पिकअप पर लदे चार मवेशियों को बरामद किया गया है, दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पशु तस्करी का प्रतीत हो रहा है। वैसे इसकी गहराई से जांच की जा रही है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

तकनीकी खामी ने बिगाड़ी फार्मर रजिस्ट्री की रफ्तार, किसान रहे दिनभर परेशान

■ सरकारी योजनाओं की डिजिटल तैयारी में नेटवर्क बना बाधा, शिविर में सीमित पंजीकरण

केटी न्यूज/चौसा

किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाने की कवायद मंगलवार को तकनीकी अवरोध के कारण प्रभावित हो गई। चौसा नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में भारी संख्या में किसान पहुंचे, लेकिन सर्वर और नेटवर्क की समस्या के चलते पंजीकरण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका। सुबह से ही कृषि भवन परिसर में किसानों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। किसान फार्मर रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें भविष्य में विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पहचान से मिलने की उम्मीद है। बावजूद इसके, सर्वर डाउन रहने के कारण अधिकांश समय पंजीकरण ठप रहा, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई किसान मायूस होकर बिना पंजीकरण कराए ही लौटने को मजबूर हुए।

सीमित समय में हुआ नामांकन

सूत्रों के अनुसार, दिन के मध्य कुछ समय के लिए सर्वर बहाल हुआ। इस दौरान कृषि कर्मियों ने तेजी से काम करते हुए करीब 60 किसानों का पंजीकरण पूरा कराया। लेकिन नेटवर्क की समस्या दोबारा सामने आने से प्रक्रिया फिर रुक गई। तकनीकी व्यवधान ने न केवल किसानों को परेशान किया, बल्कि शिविर में तैनात कर्मचारियों के लिए भी स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया।

डिजिटल पहचान की पहल

प्रखंड कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री राज्य और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत प्रत्येक किसान की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी दी जाएगी। यही आईडी आगे चलकर पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, अनुदान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का आधार बनेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीकी समस्या के कारण कार्य बाधित हुआ है। संबंधित उच्चाधिकारियों को सर्वर और नेटवर्क की दिक्कत से अवगत करा दिया गया है। जैसे ही समस्या का समाधान होगा, शिविर को पुनः प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा और शेष किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

किसानों में उम्मीद बरकरार

हालांकि अव्यवस्था के कारण किसानों में नाराजगी भी देखी गई, लेकिन अधिकांश किसानों का कहना था कि यदि यह पहल सही तरीके से लागू होती है तो उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सभी की निगाहें तकनीकी सुधार पर टिकी हैं, ताकि फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य जमीन पर सफलतापूर्वक उतर सके।

15वें वित्त की नाली निर्माण योजना पर सवाल, कठघरवा में उठी भ्रष्टाचार की बू

■ बोले ग्रामीण पारदर्शिता गायब, गुणवत्ता से हो रहा है खिलवाड़

केटी न्यूज/चौसा

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता की बातें कागजों तक सिमटती दिख रही हैं। चौसा प्रखंड की पवनी पंचायत अंतर्गत कठघरवा गांव में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। गांव में चल रहा यह निर्माण कार्य न केवल तय मानकों की अनदेखी कर रहा है, बल्कि इससे सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका भी गहराती जा रही है।

बिना प्राक्कलन बोर्ड, बिना जवाबदेही

सबसे गंभीर पहलू यह है कि निर्माण स्थल पर प्राक्कलन बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। इससे ग्रामीणों को यह तक जानकारी नहीं मिल पा रही कि योजना की कुल लागत क्या है, नाली की लंबाई-चौड़ाई कितनी है और किस गुणवत्ता के सामग्री का उपयोग किया जाना है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह स्थिति सिर्फ कठघरवा तक सीमित नहीं, बल्कि प्रखंड की लगभग सभी पंचायतों में यही हाल है। बिना सूचना बोर्ड के योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता पूरी तरह गायब हो चुकी है।

घटिया ईंट और कमजोर नींव से बन रहा नाला

ग्रामीणों के अनुसार गंगा पंप नहर से लगभग 250 मीटर दूरी पर बनाए जा रहे इस बड़े नाले में दो नंबर ईंटों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। नाली की समतल और मजबूती के लिए आवश्यक कंक्रीट ढलाई भी नहीं की गई है। नतीजतन, नाली की नींव कमजोर बनी हुई है, जो आने वाले बरसात में किसी भी समय ध्वस्त हो सकती है। यह न सिर्फ सरकारी धन की बबार्दी होगी, बल्कि गांव की जलनिकासी व्यवस्था भी ठप पड़ सकती है।

मसाले के अनुपात में भी खेल

स्थानीय लोगों ने निर्माण में प्रयुक्त मसाले के अनुपात पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीमेंट और बालू का मिश्रण मानकों के अनुरूप नहीं है। इससे नाली की मजबूती पर सीधा असर पड़ेगा। धर्मेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, संजय साह, शमार्नंद ठाकुर, सोपाल जी और परमानंद साह सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य केवल खानापूर्ति के लिए कराया जा रहा है।

जांच और कार्रवाई की उठी मांग

ग्रामीणों में इसको लेकर भारी आक्रोश है। लोगों ने मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी संवेदक के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, भविष्य में सभी विकास योजनाओं में प्राक्कलन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने की मांग की गई है, ताकि सरकारी धन के उपयोग पर जनता की नजर बनी रहे।

प्रशासन का जवाब

इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज पासवान ने कहा है कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसी अनियमितताओं पर वास्तव में लगाम लग सकता है।

महानगर नहीं, मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी : अविनाश दत्त

केटी न्यूज/बक्सर

दत्त क्लासेस का परिसर उस समय उत्सव और प्रेरणा के रंग में रंग गया, जब निदेशक अविनाश दत्त का जन्मदिवस छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक के साथ धूमधाम से मनाया। सैकड़ों छात्र-छात्राओं की मौजूदगी में यह आयोजन केवल जन्मदिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा, आत्मविश्वास और सही दिशा पर एक सार्थक संवाद बन गया। छात्रों को संबोधित करते हुए अविनाश दत्त ने परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए महानगरों का रुख करना अनिवार्य नहीं है। आज के दौर में इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर संचार व्यवस्था ने गांव-कस्बों के छात्रों को भी वही अवसर उपलब्ध करा दिए हैं, जो बड़े शहरों में मिलते हैं। जरूरत है तो केवल सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। हर बच्चा अपनी क्षमता और गति से आगे बढ़ता है, तुलना और दबाव से उसका मनोबल टूट सकता है। सही प्रोत्साहन और सकारात्मक माहौल ही उसकी असली ताकत बनता है। इस अवसर पर दत्त क्लासेस के छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में अमित, शिक्षा और हर्षित द्वारा 100 में 96 व 95 अंक प्राप्त करना जिले के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया। इन सफलताओं ने यह साबित कर दिया कि समर्पण और सही दिशा हो तो छोटे शहरों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने केक काटकर अपने शिक्षक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।

भोजपुर डीएम ने मेडिकल कॉलेज सहित कृषि महाविद्यालय का किया निरीक्षण

■ एजेंसियों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर दिया विशेष निर्देश

केटी न्यूज/आरा

जिला पदाधिकारी,भोजपुर तनय सुल्तानिया द्वारा निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर एवं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएँ, ताकि इस परियोजना का लाभ शीघ्र ही क्षेत्र की आम जनता को मिल सके। उन्होंने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जल-निकासी (ड्रेनेज) से संबंधित समस्याओं पर भी जिला पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन, भोजपुर, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग आरसीडी, विशेष कार्य पदाधिकारी, भोजपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उनके द्वारा निमार्णाधीन कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर एवं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने निर्माण कार्यों को सुचारु, प्रभावी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के अवसर पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अभियंताओं के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग के अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

खगौल नगर परिषद का होगा अब नया भूगोल : वार्डों के परिसीमन का खाका हुआ तैयार, प्रारूप जल्द होगा जारी

एजेंसी। पटना

राजधानी पटना जिले के क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद खगौल में वार्डों के नए सिरे से गठन और परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहली जनवरी से शुरू हुई यह कवायद अब निर्णायक मोड़ पर है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन आगामी 16 जनवरी 2026 को नए वार्डों का प्रारूप प्रकाशित करने जा रहा है। नगर परिषद खगौल के विस्तार के बाद वार्डों की संख्या और उनकी सीमाओं में बड़े बदलाव की संभावना है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वार्डों के गठन और सीमाओं के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद, 16 जनवरी को आम जनता के लिए इसका प्रकाशन किया जाएगा, ताकि लोग अपने क्षेत्र की नई सीमाओं और वार्ड नंबरों की जानकारी ले सकें। प्रशासन ने पारदर्शिता बरतने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्तियां मांगी हैं। इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव जिला निर्वाचन कार्यालय (पटना) या अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के कार्यालय में लिखित रूप में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.google.com/search?q=http://www.sec.bihar.gov.in)पर जाएं। आप अपनी बात secbihar@gmail.com या mailto:secbihar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। वार्ड गठन से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-3457-243 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतिम प्रकाशन के बाद खगौल नगर परिषद के चुनावी वार्डों की सीमाएं आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगी, जिसके आधार पर आगामी नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूची और बूथों का निर्धारण होगा। यदि आपको नए वार्ड गठन पर कोई आपत्ति है या आप सुझाव देना चाहते हैं, तो इस तिथि को ध्यान में रखें।

यदि आपको नए वार्ड गठन पर कोई आपत्ति है या आप सुझाव देना चाहते हैं, तो इस तिथि को ध्यान में रखें

वार्डों का प्रारूप प्रकाशन-	16 जनवरी, 2026
दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि-	16 जनवरी से 03 फरवरी, 2026 तक
आपत्तियों का निपटारा -	19 जनवरी से 07 फरवरी, 2026 तक
प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी का प्रकाशन-	09 फरवरी से 12 फरवरी, 2026 तक
प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन -	16 फरवरी से 20 फरवरी, 2026 तक
गजट में अंतिम प्रकाशन-	25 फरवरी, 2026 तक

प्रधानमंत्री निःशुल्क उज्ज्वला गैस योजना मिलते ही उपभोक्ताओं के चेहरे

■ निदेशक निशा बोलीं..दलालों से दूर होकर एजेंसी से स्वयं प्राप्त करें फ्री कनेक्शन

केटी न्यूज/नवादा

जिले क्षेत्र के रजौली प्रखंड मुख्यालय के सती स्थान स्थित निशा गैस एजेंसी में बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क गैस कनेक्शन के साथ गैस सिलेंडर व चूल्हा दिया जा रहा है। जानकारी के आभाव में कुछ उपभोक्ता दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और आर्थिक दोहन का शिकार हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यह अफवाह फैली हुई थी कि निशा गैस एजेंसी में कर्मियों द्वारा चूल्हे देने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ लाभुक महिलाएं एजेंसी से चूल्हा प्राप्त खुशी व्यक्त कर चितरकोली गांव निवासी पूनम कुमारी,करिगांव निवासी गीता देवी के पुत्र राहुल कुमार सिंह और महियारा गांव निवासी चंचला देवी ने बताई कि एजेंसी द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन और चूल्हा आदि दिया गया है। वहीं सिया देवज, कैलाशी देवी, सुबीना खातून, मुन्नी देवी एवं संजू देवी समेत दर्जनों महिलाओं ने बताई कि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले चूल्हे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि होरीला गांव में बीते कुछ माह पूर्व उज्ज्वला योजना के तहत मिले चूल्हे का उपयोग करने के दौरान दुर्घटना घटी थी,जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद उपभोक्ताओं द्वारा योजना के तहत मिलने वाले चूल्हे के जगह अच्छी गुणवत्ता वाले चूल्हे की मांग की जा रही है,जिसके लिए एजेंसी द्वारा नगद लिया जा रहा है और उसकी रसीद भी जा रही है। जबकि इस संबंध में गैस एजेंसी की निदेशक निशा कुमारी ने बताई कि प्रत्येक दिन 60 से अधिक उपभोक्ताओं को कनेक्शन के साथ चूल्हे आदि का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।उपभोक्ता द्वारा बीपीसीएल के द्वारा दिए जा रहे चूल्हे के जगह पर बड़ा चूल्हा लेने पर ग्राहकों को पैसा देना पड़ रहा है।संचालिका ने बीपीएल उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बिना दलाल के गैस एजेंसी पहुंचकर लाभ लें।

स्वास्थ्य : देवढी हेल्थ और वेलनेस सेंटर में चिकित्सक हुए नदारद, ग्रामीण उपचार ठप

केटी न्यूज/आरा

भोजपुर जिले के गडहनी प्रखंड अंतर्गत देवढी गांव में वर्षों पहले निर्मित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। लाखों रुपये की लागत से बना यह स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण केवल भवन बनकर रह गया है, जिससे क्षेत्र की हजारों आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र का भवन लंबे समय से तैयार है, लेकिन यहां नियमित रूप से डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है। कई बार स्वास्थ्यकर्मी या एएनएम सीमित समय के लिए आते हैं, लेकिन चिकित्सक के अभाव में मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता। गंभीर मरीजों को मजबूरन गडहनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आरा सदर अस्पताल का रुख करना पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी-खांसी, बुखार, डायरिया, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों का टीकाकरण और बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिलनी चाहिए थीं, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण अधिकांश सेवाएं कागजों तक ही सीमित हैं। आपात स्थिति में समय पर इलाज न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों व्याप्त है। देवढी गांव और आसपास के टोले-मोहल्लों की बड़ी आबादी कृषि मजदूरी पर निर्भर है। ऐसे में बार-बार प्रखंड या जिला अस्पताल जाना उनके लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से कठिन हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण सरकार की जन-स्वास्थ्य योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि देवढी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अविलंब डॉक्टर की नियमित तैनाती की जाए, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा केंद्र को पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेता है और कब तक देवढी के ग्रामीणों को उनके गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल पाता है।

एक नजर

दिनारा में आज को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

दिनारा। विभागीय आदेश के आलोक में ग्रिड के 33 केवी मेन बसबार में अतिआवश्यक मरम्मति कार्य कराने व ग्रिड से निकलने वाले सभी 33 केवी फीडर 7 जनवरी को दिन के 11 बजे से 14 बजे तक बंद रहेगी। कनीय विद्युत अभियंता दिनारा विकाश कुमार ने बताया की विद्युत शक्ति उपकेंद्र दिनारा से निकलने वाले 11 केवी दिनारा, इंदौर, राजपुर, धनपुरा एवं विद्युत शक्ति उपकेंद्र अकोढ़ी से निर्गत महेशपुर व जलवइया फीडर का विद्युत आपूर्ति 11 बजे से 14 बजे तक बंद रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल बिक्रमगंज राज कुमार के द्वारा उपभोक्ताओ से आग्रह किया गया है कि विद्युत आपूर्ति बंद होने से पहले ही बिजली संबंधित अपना जरूरी काम निपटा लेंगे। मरम्मति के दौरान तकनीकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को सुझाव दिया है कि आवश्यक घरेलू और व्यावसायिक कार्य निर्धारित समय से पहले ही निपटा लें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस रखरखाव कार्य का उद्देश्य लाइन व उपकरणों की कार्य क्षमता को दुरुस्त रखना है ताकि निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सिविल कोर्ट ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई का जारी किया आदेश

सासाराम। सासाराम सिविल कोर्ट ने अगरेर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने एक जमानत याचिका के दौरान सुनवाई करते यह आदेश जारी किया है। बताया जाता है कि आरोपी निरंजन कुमार के द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका पर जिला जज चतुर्थ सुनवाई कर रहे थे। जिसमें किशोरी पासवान ने आरोपित पर अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ उसका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। अगरेर थानाध्यक्ष द्वारा इस मामले को डकैती बताते हुए बीएनएस की धारा 309 (6) लगाया गया था एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने मामले की संदिग्धता को देखते हुए अगरेर थानाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। केस करने वाले ने कोर्ट को बताया कि आरोपित कोई हथियार नहीं लिए थे ना हीं उनका मोबाइल छीन पाए थे। कोर्ट ने पाया कि यह सिर्फ एक झड़प का मामला था, जिसे थानाध्यक्ष द्वारा जानबूझकर डकैती बनाया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर पिछले दो माह से जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट ने आरोपित को जमानत देते हुए अगरेर थानाध्यक्ष के खिलाफ डीजीपी, डीआईजी शाहाबाद एवं एसपी रोहतास को एक निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती झूठे केस में फंसाने एवं पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया।

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा मांगपत्र

गड़हनी। गरीबों और दलितों की बस्तियों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त राज्यव्यापी आह्वान पर मंगलवार को गड़हनी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन भाकपा प्रखंड सचिव राम छपित राम ने किया। धरना को संबोधित करते हुए राम छपित राम ने कहा कि भीषण ठंड में सरकार की अमानवीय बुलडोजर कार्रवाई से दलित-गरीब परिवार बेघर हो रहे हैं, जिससे उनकी जीवन-जीविका और सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजाड़कर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दे रही है, जिसके खिलाफ संगठित संघर्ष जरूरी है। धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए दलित-गरीब बस्तियों को उजाड़ने पर रोक, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के विस्थापन बंद करने, पीपीएच एक्ट 1948 के तहत पर्चा देने, आवास योजना की राशि बढ़ाने, मनरेगा की पुनर्बहाली तथा चार लेबर कोड वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन में कृष्ण कुमार निमोही, अवधेश पासवान, भीम पासवान, ओम प्रकाश सिंह, नारायण राम, प्रद्युम्न पासवान, अंबिका राम, श्याम लाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो युवक बुरी तरह जख्मी, कार चालक फरार

डेहरी। इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के बडीहा गांव के समीप मंगलवार की शाम का बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे चिंताजनक स्थिति में सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया है। घटना के बाद कार चालक कार लेकर भागने में सफल रहा। घटना के बारे में बताया जाता है, कि हीरो होंडा बाइक बीआर 26 टी 9046 से बाइक सवार बघैला थाना क्षेत्र निवासी भूपेश शाह का पुत्र करण शाह अपने एक अन्य दोस्त के साथ डेहरी से तिलौथू की तरफ जा रहा था। वही सामने से आ रहे एक अज्ञात कार ने ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार दोनों सड़क पर जहां-तहां फेंका गया। बडीहा निवासी पंच आनंद पांडे ने इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर चिंताजनक स्थिति में सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है, कि उत्तर प्रदेश राज्य के नंबर प्लेट लगे कार दुर्घटना के बाद तेजी से भागने में सफल रहा। वही समाचार लिखे जाने तक चिंताजनक स्थिति में दोनों युवकों का सदर अस्पताल सासाराम में इलाज कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था, कि सड़क के दोनों तरफ बालू की मोटी परत लगातार दुर्घटना को अंजाम देता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बालू लदे वाहनों का धड़ल्ले से परिचालन होता है। सड़कों की सफाई नहीं होने के कारण बालू की मोटी परत के कारण चिकनी सड़के सिकुड़ गई है, और आए दिन दुर्घटना हो रही है।

क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में बिहिया ने तेधरा टीम को 213 रनों से हराया

○ मुख्य अतिथि डॉ. नरेंद्र ने मैच का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों से मिले

केटी न्यूज/आरा

संघ द्वारा स्थानीय जैन कालेज आरा में आयोजित भोजपुर जिला जूनियर डिविजन क्रिकेट लीग मैच बिहिया क्रिकेट अकादमी बनाम तेधरा क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इस मैच का उद्घाटन जैन कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉ. नरेंद्र कुमार के द्वारा जैन कॉलेज, अजय कुमार तिवारी उर्फ मुनमुन तिवारी एवं सुनीत सिंह ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। जबकि बिहिया क्रिकेट अकादमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बिहिया क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में 304 रन चार विकेट खोकर बनाए। बिहिया क्रिकेट अकादमी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए रितिक ने 56 रन, आदित्य कुमार गुप्ता ने 59, रिषभ राज कश्यप ने नाबाद 74 रन, उत्कर्ष ने नाबाद 20 रन, अतिरिक्त 80 रनों का योगदान रहा। वही तेधरा क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए आयुष ने सर्वाधिक दो विकेट, तेजस ने एक विकेट प्राप्त किया। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तेधरा क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 91 रनों पर सिमट गई। तेधरा क्रिकेट क्लब की ओर से मात्र एक बल्लेबाजी शुभम कुमार ने 16 रन बनाया। बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई अंक में प्रवेश नहीं किया। बिहिया क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रियांशु ने तीन विकेट कृष , आदित्य और रौनक ने दो विकेट प्राप्त किया। एक तरफ मुकाबले में बिहिया क्रिकेट अकादमी ने तेधरा क्रिकेट क्लब को 213 रनों से पराजित किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रिषभ राज कश्यप को चुना गया। मैच के दौरान,भोजपुर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष विवेक कुमार, भोजपुर जिला क्रिकेट संघ के लीग संयोजक रत्नेश नन्दन, आकाश कुमार उपस्थित थे।इस आशय की जानकारी भोजपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव आलोक कुमार ने दी। इस मैच को सुचारू रूप से संचालन में सुमित सिन्हा की अहम भूमिका रही।

अंजबित सिंह महाविद्यालय में नए प्रधान सहायक ने संभाला पदभार

केटी न्यूज/रोहतास

वरीय सहायक कुमार दिनेश उर्फ अरविंद सिंह बने प्रधान सहायक अंजबित सिंह कॉलेज बिक्रमगंज में निवर्तमान कार्यकारी प्रधान सहायक के सेवा निवृत होने के बाद आज कार्यालय में वरीय सहायक कुमार दिनेश उर्फ अरविंद सिंह को प्रधानाचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राम ने प्रधान सहायक का प्रभार दिया। ज्ञातव्य हो कि 31 दिसंबर 2025 को कार्यकारी प्रधान सहायक सेवा निवृत हुए। क्रिसमस की छुट्टि के बाद 2 जनवरी 2026 को महाविद्यालय खुला। लेकिन प्रधान सहायक का पद अब तक रिक्त था। फलस्वरुप प्रधानाचार्य ने तत्काल वरीयता सूची के आधार पर कुमार दिनेश को प्रधान सहायक का प्रभार संबंधित अधिसूचना जारी की। प्रधानाचार्य कक्ष में कुमार दिनेश को बुके और फूल माला से प्रधानाचार्य सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि कुमार दिनेश पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सबको साथ लेकर महाविद्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। इसके बाद कुमार दिनेश को कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और सचिव अक्षय कुमार प्यारे जी ने उनके कक्ष में सम्मान पूर्वक बैठाया। मौके पर डॉ. कन्हैया सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल कुमार, डॉ. प्रभात कुमार, कर्मी संघ अध्यक्ष अरुण सिंह,डॉ.भरत प्रसाद, डॉ.सरोज राम, डॉ.अखलाक अहमद फैजल अहमद, डॉ. परवेज अहमद ,अशोक कुमार सिंह, संकेश्वर सिंह, डॉ. आरके पांडे व लेखापाल विनोद कुमार सिंह, मनोज कुमार, संतोष पांडेय,आरजू खान,सत्येश्वर राम, अजय गुप्ता, दीपक कुमार, सतीश ,संतोष ,मिंटू कृष्णा प्रसाद सहित समस्त महाविद्यालय कर्मी उपस्थित थे।

website:keshavtimes.com
e-mail:keshavtimes1@gmail.com

पीडीएस राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब गेहूं और चावल दोनों मिलेंगे

एजेंसी। पटना

जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लाभुकों को संतुलित, पोषणयुक्त और विविध खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव राज्य सरकार की नई नीति के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले कई क्षेत्रों में लाभुकों को केवल चावल या सीमित मात्रा में अनाज मिल पाता था, जिससे पोषण की दृष्टि से संतुलन नहीं बन पाता था। अब गेहूं और चावल दोनों का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) श्रेणी के सभी लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा। इससे पहले कई लाभुकों की शिकायत रहती थी कि उन्हें केवल एक ही प्रकार का अनाज मिल रहा है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। गेहूं और चावल दोनों मिलने से परिवारों के भोजन में विविधता आएगी और पोषण स्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित मात्रा से कम या अधिक राशन नहीं दिया जाएगा। राशन वितरण पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और ई-पास मशीन के माध्यम से सभी लेन-देन दर्ज किए जाएंगे। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने लाभुकों से अपील की कि वे राशन लेते समय ई-पास मशीन से प्राप्त पर्ची अवश्य लें और मौके पर ही अनाज की मात्रा और गुणवत्ता की जांच कर लें। यदि किसी दुकान पर कम राशन देने, अतिरिक्त राशि वसूलने या किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत होती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या संबंधित वरीय अधिकारियों को दें। शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने आगे बताया कि जनवरी माह से राशन वितरण के साथ-साथ लाभुकों के ई-केवाईसी (ई-केवाईसी) और सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लाभुकों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

बिहार के सभी डीएम को डिप्टी सीएम का सख्त फरमान एसपी के साथ जमीन माफियाओं की लिस्ट बनाएं

एजेंसी। पटना

भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भू-माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अब जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं की जड़ में भू-माफिया की गहरी पैठ एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में सक्रिय भू-माफिया की सूची पुलिस अधीक्षक के सहयोग से अविलंब तैयार कर मुख्यालय भेजें। उन्होंने साफ कहा कि सूची मिलते ही सरकार के स्तर पर ठोस और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान केवल कागजी नहीं होगा, बल्कि जमीन पर असर दिखेगा, ताकि आम नागरिक बिना भय के अपनी जमीन से जुड़े अधिकारों का उपयोग कर सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सभी प्रमुख सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना है। हालांकि, ऑनलाइन प्रक्रिया में आम लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर अंचल कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोलने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर कंप्यूटर प्रशिक्षित वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) मामूली शुल्क पर न सिर्फ आवेदन करेंगे, बल्कि सही परामर्श भी देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति तकनीकी वजहों से वंचित न रह जाए।उप मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी कामों में बाधा डालने वाले तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे फर्जी कागजात या गलत मंशा से कार्य बाधित करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकें। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि इस अधिकार का निर्भीक और सही दिशा में उपयोग करते हुए भू-माफिया और दलालों को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई करें। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के उद्देश्यों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पटना के ज्ञान भवन में राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारियों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दो टूक कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी ही शासन की बुनियाद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के बिचौलिये, दलाल या भू-माफिया की संलिप्तता अब स्वीकार्य नहीं होगी। सही और वैध व्यक्ति को किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल भी उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय योजनाओं और सुधारात्मक कदमों की जानकारी साझा की और भरोसा दिलाया कि सरकार आम जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनकल्याण संवाद में बड़ी संख्या में आम लोग और अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की इस पहल का स्वागत किया।

एक नजर

बिहार में चिमनी में ब्लास्ट, हादसे में तीन लोग बुरी तरह झुलसे, 50 लाख का नुकसान

हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर में आज चांदपुर स्थित ह्यकिंगह्न ईंट भट्ठा में पूजा पाठ के दौरान आग लगाने के तुरंत बाद चिमनी ब्लास्ट हो गया। हादसे में दो फायरमैन और भट्ठा का स्थानीय मैनेजर बुरी तरह झुलस गए। ब्लास्ट के बाद तीनों जख्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि भट्ठा में ईंट तैयार करने के लिए आग लगाई जा रही थी और चिमनी लगभग ८० फीट ऊंची थी। आग लगाने के दौरान डीजल का प्रयोग किया गया था, जिससे अचानक ब्लास्ट हो गया। एघटना के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, और सूचना मिलने पर बिदुपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। चिमनी मालिक ने बताया कि हादसे में लगभग 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है।

बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

पटना। बिहार में मॉब लिंचिंग और धार्मिक आधार पर हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सख्त संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने मुख्य सचिव और बिहार पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखकर कई अहम मांगें की हैं। आयोग ने अफवाहों और धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को ह्लबांग्लादेशीह्न बताकर हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। पत्र में नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और मधुबनी में हुई मॉब लिंचिंग और हमलों का उल्लेख किया गया है। आयोग ने हर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मॉब लिंचिंग की सूचना मिलने पर तत्काल त्र्क्रक्र दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने, पीड़ितों और उनके परिवार को तुरंत राहत व मुआवजा देने पर जोर दिया गया है। पत्र में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की मांग भी की गई है। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आयोग ने राज्य सरकार से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को सौंपने का भी आग्रह किया है।

बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर, अब धान खरीद पर 24 घंटे के अंदर होगा भुगतान

पटना। बिहार सरकार पूरे राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर रही है। इस दौरान किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिन किसानों का भुगतान किसी कारण से लंबित रह गया है उनका भुगतान तुरंत करने का निर्देश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने दिया है। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने मंगलवार 6 जनवरी को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मुख्यालय में निगम की समीक्षा बैठक यह निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि, जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनका भुगतान त्र्क्लह्म (त्र्१२३ क्ल्ल त्र्१२३ ड४३) व्यवस्था के तहत शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही, मिलों के निबंधन एवं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) से जुड़े विषयों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है कि 10 जनवरी 2026 तक मिलों से प्राप्त एफआरके सैंपलों की जांच अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए, जिससे गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित योजनाओं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, गेहूं आधारित पोषण योजना, किशोरियों के लिए योजना तथा कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि इन योजनाओं के सफल संचालन में बीएसएफसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

शिवहर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

शिवहर के पुरनहिया अंचल में निगरानी विभाग ने दाखिल-खारिज के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को ट्रैप किया। बिहार में आए दिन घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हम नहीं सुधरेंगे की मानो कसम ही खा ली है। यही कारण है कि निगरानी की कार्रवाई के बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बिहार के शिवहर जिले से सामने आई है जहां विजिलेंस की टीम ने एक और घूसखोर को दस हजार रुपए घूस लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरनहिया अंचल के राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी को 10 हजार रुपये घूस लेते हुए ट्रैप किया गया।जानकारी के अनुसार, राजस्व कर्मचारी दाखिल-खारिज के काम के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

नेपाल गए बिहार के तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की गई जान

एजेंसी। पटना

नव वर्ष की शुरूआत ईश्वर की भक्ति से करने निकले बलिया के तीन युवक अपने घरों में फिर कभी लौटकर नहीं आए। "पूजा कर के जल्दी लौट आएंगे घर से निकलते वक्त यही शब्द थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह तीन दोस्तों की आखिरी विदाई होगी। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा-पाठ के लिए गए बलिया के तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत की खबर ने पूरे इलाके को अंदर तक हिला दिया है। जिन घरों में कुछ दिन पहले नए साल की खुशियां थीं, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। परिजनों के अनुसार 4 जनवरी की शाम करीब 4 बजे तीनों से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। आवाजों में सामान्य खुशी थी। इसके बाद फोन बंद हुआ, संदेश नहीं पहुंचे और हर गुजरता घंटा बेचैनी बढ़ाता गया। पूरी रात इंतजार के बाद जब अगले दिन भी कोई सूचना नहीं मिली, तो परिजनों ने इंटरनेट पर तलाश शुरू की। नेपाली मीडिया में सड़क हादसे की खबर देखकर परिजनों के हाथ कांप उठे- और तभी सच सामने आ गया। इस हादसे ने बलिया के तीन परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। गिट्टू कुमार, अरविंद कुमार उर्फ भाई जी और रजनीश कुमार उर्फ गोल्डन- तीनों अपने-अपने परिवार के मजबूत सहारे थे। कोई व्यवसाय संभाल रहा था, कोई दुकान चला रहा था, तो कोई पिता के साथ खेती-बाड़ी में हाथ बंटाता था। आज तीनों घरों में चूल्हे ठंडे हैं और आंखें सूखने का नाम नहीं ले रहीं। मृतकों की पहचान बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मेंसेरपुर पंचायत के शादीपुर करारी निवासी अधिवक्ता रमेश सिंह के 40 वर्षीय पुत्र गिट्टू कुमार, लखमीनिया स्टेशन रोड स्थित सेठानी धर्मशाला के निवासी मदन मोहन प्रसाद के 44 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार उर्फ गोल्डन तथा स्वर्गीय मोहन दास के 50 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार उर्फ भाई जी के रूप में हुई है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा नियुक्ति के तीन दिन बाद ही आलोक राज ने छोड़ी कुर्सी

एजेंसी। पटना

पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बिहार एसएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष की कुर्सी पद बैठने के तीन दिनों के अंदर उन्होंने इस्तीफ दे दिया। पूर्व डीजीपी 'आलोक राज' ने अमर उजाला से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों ऐसी थी कि मैंने इस्तीफा दे दिया। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हालांकि, जिस तरह डीजीपी बनाने के बाद उनसे वह पद रिटायरमेंट के पहले ही छीन लिया गया था, उसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद सरकार के किसी पद को नहीं लेंगे। आश्चर्यजनक रूप से सरकार ने रिटायरमेंट के साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्थाई अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की अधिसूचना जारी की थीएक जनवरी को नीतीश सरकार ने की थी घोषणा

एक जनवरी को 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाने की घोषणा नीतीश सरकार ने की थी। अब अचानक इतने कम समय में उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। दिसंबर 2024 में नीतीश सरकार ने उन्हें बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया था। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर ही राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया था। तब से वह 31 दिसंबर 2025 तक बीएसएससी अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में रहे। इसके बाद वह सेवानिवृत्व हुए और सरकार ने उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन, कुर्सी पर बैठने के तीन दिन के अंदर ही उन्होंने पद का त्याग कर दिया।

सावधान! बिहार में 4.6 डिग्री तक पहुंचा पारा, तीन दिनों में और बढ़ेगी ठंड

एजेंसी। पटना

बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भागलपुर, गया, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर समेत कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। इन जिलों का तापमान गिरकर पांच डिग्री तक पहुंच गया। भागलपुर के सबौर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज सुबह पटना, पूर्णिया समेत कुछ जिलों में धूप जरूर निकली लेकिन सर्द हवा के कारण लोग धूप में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर, पश्चिम चंपारण, गया समेत कुछ जिले घने कोहरे की चादर में लिपट चुके हैं। पटना के मौसम की बात करें तो यहां पर आज सुबह धूप निकली है। इसलिए अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक जाने के आसार हैं। वहीं आज का न्यूतनम तापमान नौ डिग्री तक रहने के आसार हैं। 10 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटे में भागलपुर का सबौर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं गया का पांच डिग्री, नालंदा का 5.5 डिग्री, सीवान का 5.7 डिग्री सेल्सियस, समस्तीपुर का 6.3 डिग्री, औरंगाबाद का 6.4 डिग्री, पश्चिमी चंपारण का 6.6 डिग्री, सारण का 6.8 डिग्री, रोहतास का सात डिग्री, अरवल का 7.3डिग्री, पूर्णिया और दरभंगा का 7.7 डिग्री, पटना का 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों का ये मौसम आपकी सेहत के लिए भी कई तरह की चुनौतियां बढ़ाने वाला हो सकता है। विशेषतौर पर ये मौसम दिल के मरीजों के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। बढ़ती ठंड के कारण हृदय के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है, धमनियां सख्त हो जाती हैं जिसके चलते हार्ट अटैक होने का जोखिम भी कई गुना बढ़ जाता है। तापमान गिरने के साथ शरीर की कार्यप्रणाली में ऐसे बदलाव होते हैं, जो सीधे हृदय पर असर डालते हैं।

इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गया, मधुबनी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज सुबह कोहरे का असर भी देखने को मिला। सबसे कम दृश्यता गया में 100 मीटर दर्ज की गई। सुबह के समय कई इलाकों में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहा।

तीन दिनों में चार डिग्री तक गिर सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। तापमान के रुख को लेकर विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में स्थिरता आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

बिहार के सरकारी स्कूलों में बदलेगी मिड डे मील की थाली, नीतीश सरकार ने जारी किए निर्देश

एजेंसी। पटना

ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अहम कदम उठाया है। जनवरी और फरवरी माह में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें पोषण की अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अंडा और मौसमी फल की अस्थायी दरें तय कर दी हैं। यह नई दर केवल दो महीनों–जनवरी और फरवरी–के लिए लागू होगी। बाकी महीनों में पहले से निर्धारित दर ही प्रभावी रहेगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि जनवरी और फरवरी में अंडा और मौसमी फल की खरीद अधिकतम छह रुपये प्रति यूनिट की दर से की जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में इससे कम दर पर अंडा या फल उपलब्ध हो, वहां कम कीमत पर ही खरीद की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि सर्दी के मौसम में बच्चों को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। अंडा और मौसमी फल न केवल उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि पढ़ाई में एकाग्रता और शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं।